

## मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण

### क. राजकोषीय संकेतक - सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में चल लक्ष्य

	(मौजूदा बाजार मूल्य पर)			
	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	के लिए लक्ष्य	
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1. प्रभावी राजस्व घाटा	2.9	1.8	1.0	0.0
2. राजस्व घाटा	4.4	3.4	2.8	2.0
3. राजकोषीय घाटा	5.9	5.1	4.5	3.9
4. सकल कर राजस्व	10.1	10.6	11.1	11.7
5. वर्ष के अंत में कुल बकाया देनदारियाँ <sup>2</sup>	45.7	45.5	44.0	41.9

#### टिप्पणी:—

1. "स.घ.उ." से आशय 2004-05 से नई श्रृंखला के अनुसार मौजूदा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद है।
2. "कुल बकाया देनदारियों" में वर्तमान विनिमय दरों पर विदेशी सरकारी ऋण शामिल है। अनुमान के लिए अचल विनिमय दरें परिकल्पित हैं। देनदारियों में एनएसएसएफ तथा एमएसएस देनदारियाँ, जो कि केंद्रीय सरकारी घाटे के वित्तपोषण के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती हैं, शामिल हैं।
3. तेरहवें वित्त आयोग की कार्ययोजना से तुलना अनुबंध-1 में दर्शाई गई है।

1. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान चुनिंदा राजकोषीय संकेतकों का निष्पादन और उपर प्रस्तुत आगामी वित्तीय वर्षों के लिए चल लक्ष्य 2011-12 के बजट में किए गए पूर्वानुमान में चूक दर्शाते हैं। दो वित्तीय वर्षों 2008-09 और 2009-10 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में वित्तीय उठा पठक देखने के बाद, 2011-12 का बजट 2010-11 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के मजबूत पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया था। 2011-12 के बजट में यह परिकल्पना की गई थी कि 2010-11 में 8.5 प्रतिशत की उस समय अनुमानित वृद्धि की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9 प्रतिशत की वृद्धि होगी। तथापि, बजट प्रस्तुत करने के बाद, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि तथा घरेलू अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति का परिदृश्य बने रहने सहित विश्व भर के घटनाक्रम ने, सरकार को उभरती हुई चुनौतियों का निराकरण करने हेतु 2011-12 के दौरान नीतिगत दृष्टिकोण में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए विवश किया।

2. बजट अनुमानों की तुलना में, 2011-12 के दौरान राजकोषीय निष्पादन का विश्लेषण करने से पूर्व, यह वांछनीय होगा कि फरवरी 2011 के बाद, भारतीय और विश्व अर्थव्यवस्था में कुछ वृहत्-आर्थिक पैरामीटरों में महत्वपूर्ण बदलावों पर नजर डाली जाए। पहला, अन्तर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों का मुद्दा है; बजट प्रस्तुत करते समय जहां यह 85 से 90 अमरीकी डालर प्रति बैरल के इर्द-गिर्द चल रही थी, वहीं कलेंडर वर्ष 2011 के अधिकांश

भाग के दौरान यह 110 से 115 अमरीकी डालर प्रति बैरल पर बनी रही। घरेलू अर्थव्यवस्था में निरन्तर चल रही उच्च मुद्रास्फीति के साथ-साथ, इसने जून, 2011 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर अप्रत्यक्ष करों और शुल्कों में कटौती को आवश्यक बना दिया। इसका राजकोषीय प्रभाव वार्षिक रूप से 49,000 करोड़ रुपए और वर्ष 2011-12 के शेष भाग के दौरान 36,750 करोड़ रुपए का था। केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से को गणना में लेने के बाद, केन्द्रीय सरकार के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर परित्याग 26,000 करोड़ रुपए का था। तथापि सेवा कर में अनुमान से बेहतर संग्रहण के परिणामस्वरूप सं.अ. 2011-12 में समग्र अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में कोई कमी नहीं आई। पेट्रोलियम उत्पादों पर उपरोक्त शुल्क कटौतियों के जरिए दी गई राहत के बावजूद, पेट्रोलियम उत्पादों के मद में सब्सिडी अभी भी ब.अ. 2011-12 की तुलना में सं.अ. 2011-12 में 45,000 करोड़ रुपए तक बढ़ गई। इसके अतिरिक्त, ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के फलस्वरूप ब.अ. 2011-12 की तुलना में सं.अ. 2011-12 में 17,201 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देनी पड़ी।

3. दूसरा, अर्थव्यवस्था में वृद्धि, जो 2009-10 और 2010-11 के दौरान 8.4 प्रतिशत की मजबूती पर थी, में मंदी के लक्षण दिखाई देने शुरू हुए और इसमें 2011-12 की पहली तीन तिमाहियों में क्रमशः 7.7 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि दर में इस गिरावट का प्रभाव 2011-12 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रहण पर

पड़ा और ब.अ. 2011-12 के स्तर की अपेक्षा सं.अ. 2011-12 में 32,000 करोड़ रुपए की कमी होने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप केन्द्र के निवल कर राजस्व में लगभग 22,800 करोड़ रुपए की कमी होगी। अतः सकल कर राजस्व के ब.अ. 2011-12 में सघउ के 10.4 प्रतिशत से सं.अ. 2011-12 में सघउ के 10.1 प्रतिशत तक की गिरावट आने का अनुमान है।

4. तीसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था में जहां मंदी के लक्षण दिखाई दे रहे थे, वहीं विश्व अर्थव्यवस्था का परिदृश्य भी बदतर था और विश्व अर्थव्यवस्था में व्याप्त अनिश्चितता ने भारतीय पूंजी बाजार में अस्थिरता पैदा की। सरकार को अपने विनिवेश कार्यक्रम को पुनः अंशोधित करना पड़ा और तदनुसार ब.अ. में 40,000 करोड़ रुपए की तुलना में 2011-12 के दौरान 13,895 करोड़ रुपए उगाहे गए हैं।

5. उपर्युक्त मदों के ही परिणामस्वरूप लगभग 1,37,000 करोड़ रुपए की समग्र कमी हुई जो सघउ का 1.5 प्रतिशत बनता है। तथापि अन्य व्यय पर बेहतर नियंत्रण से, राजकोषीय घाटा सं.अ. 2011-12 में सघउ के 5.9 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है, जो ब.अ. 2011-12 की तुलना में सघउ की 1.3 प्रतिशत की वृद्धि है। कर राजस्व प्राप्ति में कमी और व्यय में मुख्यतया सब्सिडी में वृद्धि के कारण, राजस्व घाटा ब.अ. 2011-12 में सघउ के 3.4 प्रतिशत से सं.अ. 2011-12 में 4.4 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। यद्यपि राजकोषीय घाटा सघउ के 1.3 प्रतिशत तक बढ़ा, केन्द्र सरकार की ऋण और देनदारियों में 2010-11 में 46.0 प्रतिशत से सं.अ. 2011-12 में 45.7 प्रतिशत की मामूली कमी आई। यह कमी मुख्यतया 2011-12 के दौरान अभिहित सघउ में अनुमान की अपेक्षा उच्चतर वृद्धि के कारण थी।

6. राजकोषीय घाटे में वृद्धि को सरकार की तेल और उर्वरक कम्पनियों को नकद सब्सिडियों के बदले में सरकारी प्रतिभूतियां जारी न करने की 2010-11 के दौरान आरंभ की गई नीति को जारी रखने के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार को 2010-11 के दौरान 3जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी से सघउ के लगभग 0.9 प्रतिशत का अनुमान से अधिक गैर-कर राजस्व का लाभ भी था। इस अतिरिक्त प्राप्ति को घटाकर, राजकोषीय घाटा 2010-11 में सघउ का 5.8 प्रतिशत हुआ होता। यदि इस घाटे को उपरोक्त संदर्भ में देखा जाए तो यह चूक इतनी विकट नहीं है; तथापि घाटे के इस स्तर को आगामी वर्षों में वहनीय स्तर तक नीचे लाने की आवश्यकता है। आगामी वर्ष में सरकार की राजकोषीय नीति उपर्युक्त सिद्धांत द्वारा दिशा निर्देशित होगी। राजकोषीय समेकन की दिशा में इसकी प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु सरकार एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन ला रही है, जिसके ब्यौरे राजकोषीय नीति रूपरेखा विवरण में दिए गए हैं।

7. वर्ष 2011-12 से, नया राजकोषीय संकेतक, अर्थात् प्रभावी राजस्व घाटा शुरू किया गया है। यह संकेतक राजस्व खाते में असंतुलन के संरचनात्मक घटक को परिलक्षित करता है। जोर इस बात पर है कि 2014-15 तक प्रभावी राजस्व घाटा समाप्त कर

दिया जाए और उसके पश्चात् निवेश और पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिए (पूंजीगत आस्तियों के सृजन, हेतु अनुदानों सहित) संसाधन बढ़ाए जाए। चुनिंदा राजकोषीय संकेतकों हेतु चल लक्ष्यों में, इस घटक को मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में शामिल किया गया है।

8. सघउ से कर अनुपात में 2007-08 के दौरान 11.9 प्रतिशत के उच्च स्तर से 2008-09 में 10.8 प्रतिशत और 2009-10 में सघउ के 9.7 प्रतिशत की तीव्र गिरावट देखी गई। 2010-11 के दौरान प्रोत्साहन उपायों की आंशिक वापसी से इस प्रवृत्ति में बदलाव आया और सघउ से कर का अनुपात 2010-11 में 10.3 प्रतिशत हो गया। तथापि, 2011-12 के दौरान अर्थव्यवस्था में विकास की मंदी और पेट्रोलियम उत्पादों पर दी गई छूटों के कारण, सकल कर राजस्व 2010-11 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 13.7 प्रतिशत की न्यूनतर वृद्धि दर पर बढ़ने का अनुमान है। तदनुसार, सघउ से सकल कर के अनुपात में बजट अनुमान 2011-12 में 10.4 प्रतिशत के अनुमानित स्तर से संशोधित अनुमान 2011-12 में 10.1 प्रतिशत की गिरावट दिखाई देती है। प्रोत्साहन उपायों को आगे और वापस लेने से, सघउ के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व के 2012-13 के 10.6 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है।

9. ब.अ. 2011-12 के कर-भिन्न राजस्व अनुमानों में, दूर संचार स्पेक्ट्रम और एफएम फेज-III की नीलामी से क्रमशः 13,000 करोड़ रुपए और 1600 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान था। तथापि इस वित्तीय वर्ष के दौरान ये नीलामियां नहीं हो पाई हैं, उपर्युक्त दो मदों से 14,600 करोड़ रुपए की कमी के बावजूद कर भिन्न राजस्व में ब.अ. 2011-12 में, 1,25,435 करोड़ रुपए से सं.अ. 2011-12 में 1,24,737 करोड़ रुपए की मामूली गिरावट आने का अनुमान है। यह मुख्यतया सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश के रूप में अनुमान से अधिक प्राप्तियों के कारण है।

10. विनिवेश से होने वाली आय, जो ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, के बजट अनुमान 2011-12 में 40,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था। तथापि, विश्व अर्थव्यवस्था में व्याप्त अनिश्चितता ने भारतीय पूंजी बाजार के निष्पादन को प्रभावित किया, सुस्का की ओर पलायन के परिदृश्य में 2011-12 के दौरान रुपए का अवमूल्यन हुआ और पूंजी बाजार अस्थिर रहा। सरकार को 2011-12 के दौरान अपने विनिवेश कार्यक्रम को संशोधित करना पड़ा और तदनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश से अनुमानित प्राप्तियों को सं.अ. 2011-12 में घटाकर 13,895 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों को गणना में लेने के बाद, कुल ऋण भिन्न पूंजी प्राप्ति ब.अ. 2011-12 में 55,020 करोड़ रुपए से घटकर सं.अ. 2011-12 में 29,751 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

11. कुल व्यय जो ब.अ. 2011-12 में 12,57,729 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, बढ़कर 13,18,720 करोड़ रुपए हो गया है जो समग्र तौर पर 60,991 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्यतया खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर मुख्य सब्सिडियों

में वृद्धि के कारण है, जिसमें 74,292 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई थी। ब.अ. 2011-12 की तुलना में सं.अ. 2011-12 में ब्याज अदायगी में 7,632 करोड़ रुपए और रक्षा सेवा व्यय में 6,522 करोड़ रुपए की वृद्धि होने से, उपर्युक्त तीनों मदों पर अनुमानित व्यय में कुल वृद्धि 88,446 करोड़ रुपए होगी। यह दर्शाता है कि उपर्युक्त तीनों मदों को छोड़कर व्यय की अन्य मदों में 27,455 करोड़ रुपए की निवल बचत हुई है। व्यय वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु वांछित कार्रवाई सब्सिडियों पर खर्च को कम करना तथा राजकोषीय घाटे को कम करके ब्याज अदायगी में वृद्धि को काबू में करना होगा।

12. वित्त व्यवस्था के पक्ष में, 2011-12 में वर्ष के दौरान लघु बचत संग्रहणों में कमी दिखाई दी। यद्यपि 1 दिसम्बर, 2011 से लघु बचत लिखतों की दरों को प्रचलित बाजारों दरों से जोड़ दिया गया है, तो भी ब.अ. 2011-12 की तुलना में सं.अ. 2011-12 में राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से वित्त संग्रहण में 34,484 करोड़ रुपए की कमी होगी। इसके अतिरिक्त, 2010-11 में अनुमान से कम संग्रहण की वजह से, एनएसएसएफ में ऋणात्मक शेष दिखाई दिया जिसका प्रभाव सरकार के इति नकदी शेष पर पड़ा। इसके परिणामस्वरूप, 20,000 करोड़ रुपए की अनुपलब्धता रही, जिनके 2011-12 के घाटे के वित्तपोषण में नकदी के आहरण द्वारा कमी के रूप में प्रयोग किए जाने का अनुमान था। राजकोषीय घाटा ही बजट अनुमान 2011-12 की तुलना में सं.अ. 2011-12 में समग्र तौर पर 1,09,163 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है, उपर्युक्त कारकों के परिणामस्वरूप क्रमशः 92,872 करोड़ रुपए और 1.01 लाख करोड़ रुपए की दिनांकित प्रतिभूतियों और राजकोषीय हुंडियों की नीलामी के माध्यम से सरकार के निवल बाजार उधारों में वृद्धि हुई। आगामी वर्ष (2012-13) की पहली तिमाही के दौरान, जब विद्यमान ऋण स्टॉक का उच्च स्तर पर मोचन किया जाना है, उभरती हुई नकदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी उधार के स्तरों को बढ़ाया गया। (राजकोषीय दृष्टिकोण वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए)।

### 2012-13 से 2014-15 तक के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण

13. सरकार ने 2008-09 और 2009-10 में दो मुश्किल भरे वित्तीय वर्षों में हिचकिचाहट के बाद 2010-11 में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया पुनः आरंभ की। हालांकि, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता ने भारत में वृद्धि की प्रवृत्ति को भी प्रभावित किया और इस प्रक्रिया को 2011-12 के दौरान रोकना पड़ा था। यह मानते हुए कि हासकारी वृद्धि 2011-12 में नीचे से उठी है और अर्थव्यवस्था के पिछले वर्ष की वृद्धि दर से उच्च होने की संभावना को देखते हुए 2012-13 की राजकोषीय नीति तैयार की गई है। राजकोषीय समेकन प्रक्रिया पर ध्यान वापस लाते हुए सरकार ने राजकोषीय घाटे को 2011-12 के संशोधित अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत से कम करके 2012-13 के बजट अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के 5.1 प्रतिशत तक लाने के उपाय शुरू किए हैं। राजकोषीय घाटे में 0.8 प्रतिशतांक की यह

कमी मोटे तौर पर राजस्व चालित है। कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद की क्रमशः 0.5 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत है। जबकि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर में वृद्धि मुख्यतया अप्रत्यक्ष करों में और प्रोत्साहन पैकेज से पीछे हटने के कारण और कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी से 40,000 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्तियों के कारण है।

14. वर्ष 2012-13 के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सकल घरेलू उत्पाद के 4.2 प्रतिशत और 2011-12 की एमटीएफपी विवरणी लक्षित सकल घरेलू उत्पाद के 4.1 प्रतिशत से अधिक है। उच्च घाटे को संभावित वृद्धि दर से अर्थव्यवस्था में वृद्धि में मंदी के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। इसके साथ ही 13वीं वित्त आयोग के अनुशंसित स्तर से राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत की गिरावट 2012-13 के बजट में मानी गई अनुशंसित ऋण - भिन्न पूंजी प्राप्तियों की तुलना में कमी के परिप्रेक्ष्य में देखी जा सकती है। हालांकि 13वें वित्त आयोग ने अपनी अनुशंसित राजकोषीय कार्ययोजना में 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.8 प्रतिशत की ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों का अनुमान लगाया था, इसके 2012-13 के बजट अनुमान में विनिवेश प्राप्तियों से सकल घरेलू उत्पाद के 0.3 प्रतिशत सहित सकल घरेलू उत्पाद के 0.4 प्रतिशत होने का अनुमान है।

15. वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान केंद्र सरकार के कुल ऋण और देनदारियों पर राजकोषीय घाटे का अनुमानित स्तर से अधिक होने का प्रभाव अंशतः 2010-11 में बेहतर निष्पादन और 2010-11 और 2011-12 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में उच्च सांकेतिक वृद्धि के कारण बराबर किया गया है। यह याद दिलाया जा सकता है कि जबकि 13वें वित्त आयोग द्वारा 2010-11 के लिए अनुशंसित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.7 प्रतिशत था, इस वर्ष का वास्तविक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2010-11 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 18.8 प्रतिशत की उच्च सांकेतिक वृद्धि के साथ दोहरा लाभ रहा कि केंद्र सरकार के कुल ऋण और देनदारियां 13वें वित्त आयोग के सकल घरेलू उत्पाद के 53.9 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में गिरकर 46 प्रतिशत हो गई हैं। वर्ष 2011-12 के संशोधित अनुमान और 2012-13 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटे का उच्च स्तर रहते हुए भी इसके 52.5 प्रतिशत और 50.5 प्रतिशत के अनुशंसित लक्ष्य की तुलना में संबंधित वर्षों में गिरकर सकल घरेलू उत्पाद के क्रमशः 45.7 प्रतिशत और 45.5 प्रतिशत तक होने का अनुमान है।

16. जैसा कि चुनिंदा राजकोषीय संकेतकों के लुढ़कते लक्ष्यों से स्पष्ट है कि सरकार 2013-14 और 2014-15 के दौरान राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया जारी रखने में प्रतिबद्ध है। आवश्यक नीतिगत उपायों के चलते राजकोषीय घाटा गिरकर 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत और 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद का

3.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके साथ ही प्रभावी राजस्व घाटा 2012-13 के बजट अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत से गिरकर 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत होने और 2014-15 में इसके समाप्त हो जाने का अनुमान है। उपर्युक्त राजकोषीय कार्ययोजना के परिणामस्वरूप पूंजी व्यय (पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों सहित) में 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.1 प्रतिशत से ब.अ. 2012-13 में 3.6 प्रतिशत 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.8 प्रतिशत और 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.9 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यद्यपि ऊपर अनुमानित घाटे के स्तर 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 2013-14 और 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में अधिक हैं, यह अनुमान है कि ऋण और देनदारियां तब भी इन दो वर्षों के सकल घरेलू उत्पाद के 47.5 प्रतिशत और 44.8 प्रतिशत के अनुशंसित ऋण के लक्ष्य की तुलना में इन दो संबंधित वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशतांक के रूप में क्रमशः 44.0 प्रतिशत और 41.9 प्रतिशत पर नीचे रहेंगी। ऊपर इंगित कुल बकाया ऋण और देनदारियों में चालू विनिमय दरों पर विदेशी ऋण शामिल हैं और इनमें राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) और बाजार स्थिरिकरण योजना की देनदारियां, जिन्हें केंद्र सरकार के घाटे के वित्तपोषण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, शामिल नहीं हैं।

17. राजस्व घाटे के 2011-12 के संशोधित अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 प्रतिशत से गिरकर 2012-13 के बजट अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह उसी स्तर पर ही है, जैसा 2011-12 के बजट अनुमान में अनुमानित था। वर्ष 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशतांक के रूप में राजस्व घाटे को अर्थव्यवस्था में संयत वृद्धि के कारण 2012-13 के दौरान मानी गई प्रत्यक्ष कर प्राप्ति में न्यून वृद्धि और 2011-12 के बजट अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के 1.6 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.9 प्रतिशत पर उच्च सब्सिडी प्रावधान के प्रसिद्धि में देखा जा सकता है। वृद्धि दर में अनुमानित पुनरुद्धार के चलते सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्ति में सुधार होने के अनुमान हैं और राजस्व व्यय प्रबंधन में आवश्यक उपायों से राजस्व घाटा गिरकर 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.8 प्रतिशत और 2014-15 में 2.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। चूंकि राजस्व घाटे का महत्वपूर्ण अनुपात पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के प्रावधान करने के कारण है, राजस्व खाते में असंतुलन के ढांचागत स्वरूप का विश्लेषण करने के लिए सरकार के प्रभावी राजस्व घाटे को देखना प्रासंगिक होगा।

18. सकल कर राजस्व के 2011-12 के संशोधित अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के 10.1 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 के बजट अनुमान में 10.6 प्रतिशत होने का अनुमान है (वर्ष 2011-12 के संशोधित अनुमान की तुलना में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिबिंबित करते हुए)। यह वृद्धि मुख्यता अप्रत्यक्ष करों में अतिरिक्त संसाधन संग्रहण उपायों के कारण हुई है। अतिरिक्त संसाधन संग्रहण के प्रभाव को निकालने के पश्चात 2011-12 के संशोधित अनुमान की

तुलना में 2012-13 के बजट अनुमान में वृद्धि 15.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था में 2011-12 की तुलना में बेहतर वृद्धि के अनुमान के चलते यह संभव होगा कि कर- सकल घरेलू उत्पाद अनुमान में और सुधार किया जाए। मध्यावधि लक्ष्यों में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशतांक के रूप में सकल कर संग्रहण के 2013-14 में 11.1 प्रतिशत और 2014-15 में 11.7 प्रतिशत होने का अनुमान है।

19. इस विवरण में दी गई राजकोषीय समेकन की कार्ययोजना सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशतांक के रूप में कुल व्यय में कटौती और सकल घरेलू उत्पाद-कर अनुपात में सुधार के मिश्रण से बनाई गई है। विकास की ओर व्यय की प्राथमिकता दोहरा और विकासेतर व्यय में वृद्धि को कम करके कुल व्यय 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद के 14.7 प्रतिशत से गिरकर 2013-14 में 14.1 प्रतिशत और 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद के 13.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। व्यय में उपर्युक्त कटौती के रहते हुए भी आयोजना व्यय उन वर्षों में 2012-13 के बजट अनुमान जैसा ही सकल घरेलू उत्पाद के 5.1 प्रतिशत पर बनाए रखे जाने का अनुमान है और पूंजी व्यय (पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों सहित) 2012-13 के बजट अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के 3.6 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकार के कुल व्यय को उपर्युक्त अनुमानित स्तर पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

## ख राजकोषीय संकेतकों को रेखांकित करने वाली मान्यताएं

### 1. राजस्व प्राप्ति

#### (क) कर राजस्व

20. वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि की समनुरूपता की सहायता से सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व 2008 में वैश्विक आर्थिक संकट के उद्भव से पहले 2007-08 में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 11.9 प्रतिशत हो गया था। हालांकि, 2008-09 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि में मंदी और कर/शुल्क रियायतों के रूप में शुरु किए गए प्रोत्साहन उपायों के कारण यह प्रतिशतता गिरकर 2009-10 में 9.7 प्रतिशत रह गई। अर्थव्यवस्था में 2010-11 के दौरान 8.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि और प्रोत्साहन कर उपायों की अंशत बहाली के चलते यह अनुपात सुधरकर 2010-11 के दौरान 10.3 प्रतिशत हो गया। हालांकि यह आर्थिक पुनरुज्जीवन 2011-12 के दौरान बरकरार नहीं रहा है। एक विचार यह है कि यह सुधार वी-आकृति की बजाय उबलू-आकृति का होगा। वृद्धि में मंदन और उपभोक्ताओं को विद्यमान उच्च वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों से बचाने के उपायों के चलते सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के तौर पर कर के 2011-12 के संशोधित अनुमान में गिरकर फिर 10.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। प्रोत्साहन उपायों के अंशत: वापस लाने के रूप में प्रस्तावित अतिरिक्त संसाधन संग्रहणों को मिलाकर अर्थव्यवस्था के 2011-12 की तुलना में बेहतर करने का अनुमान है और सकल घरेलू

उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व बढ़कर 2012-13 के बजट अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के 10.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप 2011-12 के संशोधित अनुमान की तुलना में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृद्धि का यह स्तर महत्वाकांक्षी दिख सकता है यदि वर्ष के दौरान अतिरिक्त संसाधन संग्रहण उपायों के प्रभाव को घटक के रूप में माने बगैर अलग से देखा जाए। कराधान पक्ष में अतिरिक्त संसाधन संग्रहणों के प्रभाव को समंजित करने के पश्चात् अपेक्षित वृद्धि को प्राप्त करने का लक्ष्य 2011-12 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2012-13 के बजट अनुमान में 15.0 प्रतिशत होगा। इस मान्यता के चलते कि अर्थव्यवस्था 2013-14 और 2014-15 के दौरान उच्च संभावित वृद्धि के पथ पर लौटेगी, मध्यावधि दृष्टिकोण में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व 2012-13 के बजट अनुमान में 10.6 प्रतिशत से सुधरकर 2013-14 में 11.1 प्रतिशत और 2014-15 में और सुधरकर 11.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह तब भी 2007-08 के दौरान प्राप्त 11.9 प्रतिशत की तुलना में कम है।

21. वर्ष 2004-05 से 2007-08 की उच्च वृद्धि की अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां 2004-05 में 4.1 प्रतिशत से समनुरूप बढ़कर 2007-08 में 5.9 प्रतिशत हो गईं। वैश्विक आर्थिक संकट की अवधि के दौरान भी यह 2008-09 में 5.9 प्रतिशत पर चिपकी हुई थी और मामूली सी गिरकर 2009-10 में 5.8 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2010-11 के दौरान यद्यपि प्रत्यक्ष कर संग्रहण 18.1 प्रतिशत की अच्छी दर से बढ़े लेकिन उच्च मुद्रास्फीति, जिसने सकल घरेलू उत्पाद में सांकेतिक वृद्धि को बढ़ा दिया, के प्रभाव के कारण सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर संग्रहण 5.8 प्रतिशत के अपने स्तर पर ही बने रहे और इन्होंने कोई सुधार नहीं दर्शाया था। अर्थव्यवस्था के 2011-12 और 2012-13 के दौरान संभावित वृद्धि दर की तुलना में निम्न दर से बढ़ने के अनुमान से पुनः यह अनुपात 2011-12 के संशोधित अनुमान और 2012-13 के बजट अनुमान में गिरकर 5.6 प्रतिशत होना अनुमानित है। यह 2008-09 और 2009-10 के मुश्किल वर्षों के दौरान विद्यमान स्तर से भी नीचे होगा। आवश्यक उपाय करके इस प्रवृत्ति को पलटने की जरूरत होगी। यह मानते हुए कि अर्थव्यवस्था 2013-14 और 2014-15 के दौरान संभावित वृद्धि दर के आसपास लौट आएगी, इस अनुपात के सुधरकर सकल घरेलू उत्पाद के क्रमशः 6.1 प्रतिशत और 6.5 होने का अनुमान है। उपर्युक्त अनुमानित प्रत्यक्ष कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कर राजस्व को वर्षानुवर्ष आधार पर 25.2 प्रतिशत और 23.1 प्रतिशत बढ़ने की जरूरत होगी। यह भी अनुमानित वृद्धि दर 2003-04 से 2007-08 के दौरान उच्च वृद्धि की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रहण में निष्पादन के परिप्रेक्ष्य में देखी जा सकती है। ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान प्रत्यक्ष कर के प्रमुख घटकों के लिए मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर लगभग 29 प्रतिशत थी। जबकि प्रत्यक्ष कर कोड

विधायी प्रक्रिया में है यह स्मरण कराया जा सकता है कि 2010-11 में प्रत्यक्ष कर कोड के लागू करने की प्रस्तावना में आय की स्लैब मौजूदा कर दर संरचना के लिए बढ़ाई गई थी और निगम कर पर अधिभार की दर घटाई गई थी। इसने अनुपालन स्तर में सुधार करने में सहायता की थी। कराधार के विस्तार और सुधरे हुए अनुपालन के चलते कराधान की प्रभावी दर बढ़ाई जा सकती है।

22. वर्ष 2008-09 के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास में आई कमी के साथ-साथ अप्रत्यक्ष कर रियायतों के रूप में किए गए प्रोत्साहन उपायों से अप्रत्यक्ष कर वापसियों पर बुरा असर पड़ा। 2007-08 के दौरान सं.घ.उ. के प्रतिशतांक के रूप में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण 6.0 प्रतिशत था। यह तीव्रता से कम होकर 2008-09 में 4.8 में 4.5 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। 2011-12 प्रतिशत पर आ गया तथा आगे और कम होकर 2009-10 में 3.8 प्रतिशत पर आ गया था। 2010-11 के दौरान प्रोत्साहन उपायों को आंशिक रूप से वापस लेने और अर्थव्यवस्था फिर से 8.4 प्रतिशत की विकास दर पर आने के चलते यह अनुपात बेहतर होकर 2010-11 में 4.5 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। 2011-12 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर सं.घ.उ. के 0.4 प्रतिशत तक रियायतें दिए जाने के बावजूद सं.घ.उ. के प्रतिशतांक के रूप में अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां 2011-12 सं.अ. में सं.घ.उ. के 4.5 प्रतिशत के स्तर पर बनी रहीं। राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया जारी रखने के लिए अप्रत्यक्ष कर राजस्व को अधिक योगदान करना होगा और कम से कम संकट-पूर्व के स्तर पर पहुंचना होगा। ब.अ. 2012-13 में एआरएम उपायों के हिस्से के तौर पर अप्रत्यक्ष करों में प्रोत्साहन उपाय आंशिक रूप से वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, यह सं.अ. 2011-12 सं.घ.उ. के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 26.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ब.अ. 2012-13 में सं.घ.उ. का 5.0 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। तथापि, वर्षानुवर्ष वृद्धि एआरएम उपायों के प्रभाव को घटाने के बाद 14.9 प्रतिशत होगी। वृद्धि का यह स्तर 2011-12 में देखी गई वृद्धि की तरह ही है, जो 2010-11 के वास्तविक स्तर के मुकाबले सं.अ. 2011-12 में 15.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। मध्यावधिक परिप्रेक्ष्य में, सं.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर वापसियां 2013-14 में 5.0 प्रतिशत और 2014-15 में 5.2 प्रतिशत होने का अनुमान है।

23. पैराग्राफ क में सारणी में दर्शाए गए ब.अ. 2012-13 के राजकोषीय संकेतक नए बजट प्रस्तावों पर आधारित हैं।

24. सकल कर राजस्व से राज्यों को दी जाने वाली राशियों में सं.अ. 2011-12 से भारी सुधार हो रहा है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राज्यों के समनुदेशन को पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर अगले वर्ष समायोजित किया जाएगा। चूंकि 2010-11 के दौरान सकल कर संग्रहण का विभाज्य पुल 2010-11 के संशोधित अनुमानों की वास्तविक प्राप्तियों से अधिक था, इसलिए राज्यों को सं.अ. 2011-12 में 2010-11 के

लिए अग्रेनीत के रूप में 2,391 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त कर राजस्व का समनुदेश दिया गया है।

25. उपकर और अधिभार तथा संग्रहण की लागत के रूप में अविभाज्य घटकों को समायोजित करने के पश्चात केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 2010-11 में 28.1 प्रतिशत से बढ़कर सं.अ. 2011-12 में 28.8 प्रतिशत हो गया। यह ब.अ. 2012-13 में कम होकर 28.4 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। तदनुसार, केंद्र सरकार का निवल कर राजस्व सं.अ. 2011-12 में सकल कर राजस्व का 71.2 प्रतिशत और ब.अ. 2012-13 में 71.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। केंद्र के हिस्से में हुई यह वृद्धि एआरएम उपायों के भाग के तौर पर अप्रत्यक्ष करों के तहत उपकर में हुई वृद्धि के कारण है। मध्यावधिक संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में यह 2013-14 और 2014-15 में भी ब.अ. 2012-13 के स्तर पर बने रहने का अनुमान है। गैर-विभाज्य घटकों में हुए किसी भारी परिवर्तन से केंद्र सरकार के अनुमानित निवल कर राजस्व पर असर होगा और अंततः घाटे के अनुमानों पर असर पड़ेगा।

### (ख) राज्यों को अंतरण

26. 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 2009-10 के 30.5 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर उनकी पंचाट अवधि 2010-15 के दौरान 32 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। इसने राजस्व खाते पर केंद्र से राज्यों को किए जाने वाले कुल अंतरणों पर सांकेतिक उच्चतम सीमा 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 39.5 प्रतिशत किए जाने की भी सिफारिश की है। इससे केंद्र सरकार के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ा है।

### (ग) कर-भिन्न राजस्व

27. कर-भिन्न राजस्व (एनटीआर) ब.अ 2011-12 में 1,25,435 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था। इसमें दूरसंचार स्पेक्ट्रम और चरण III एफएम रेडियो की नीलामियों के कारण प्राप्त हुए 14,600 करोड़ रुपये शामिल हैं। यद्यपि, ये दो नीलामियां इस वर्ष के दौरान संचालित नहीं की गई थीं और उपर्युक्त अनुमानित प्राप्तियां वसूली नहीं जा सकी थीं। उपर्युक्त कमी के बावजूद कर-भिन्न राजस्व ब.अ. 2011-12 के स्तर में मामूली सी गिरावट दर्शाकर सं.अ. 2011-12 में 1,24,737 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। 2010-11 की वास्तविक प्राप्तियों से तुलना के संबंध में, 3जी और बीडब्ल्यू स्पेक्ट्रम नीलामी से प्राप्त एक बारगी प्राप्तियों को घटाने के पश्चात सं.अ. 2011-12 में 2010-11 की वास्तविक प्राप्तियों की अपेक्षा 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है। दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी से 40,000 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्ति को शामिल करते हुए ब.अ. 2012-13 में कर-भिन्न राजस्व 1,64,614 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस प्राप्ति का अन्य प्रमुख घटक का अनुमान पीएसयू और एफआई के लाभांश और लाभों के साथ-साथ आरबीआई के अधिशेष के अंतरण, लाभ पेट्रोल और नियमित दूरसंचार प्राप्तियों से लगाया जाता है। राजस्व का यह घटक लगभग एक सा ही रहने के

कारण सरकार को विभिन्न प्रयोक्ता प्रभागों में समय-समय पर संशोधन करने के साथ कर-भिन्न राजस्व की प्राप्तियां बढ़ाने के लिए एक तंत्र विकसित करना होगा। इससे विशेषकर रेलवे और डाक की सेवा सुपुर्दगी की लागत की वसूली सुनिश्चित होगी और तदनुसार, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के लिए बजटीय सहायता पर निर्भरता में कमी आएगी। वर्ष 2013-14 और 2014-15 दोनों में दूरसंचार स्पेक्ट्रम से अनुमानित 25,000 करोड़ रुपये के कर-भिन्न राजस्व और अन्य कर-भिन्न राजस्व घटकों में 8 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के चलते यह अनुमान लगाया जाता है कि स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कर-भिन्न राजस्व ब.अ. 2012-13 में 1.6 प्रतिशत से गिरकर 2013-14 में 1.4 प्रतिशत होगा और 2014-15 में 1.3 प्रतिशत रहेगा। एक उर्ध्वगामी जोखिम हो सकता है जिसमें छोड़ी गई कोई मद सरकार के लिए अधिक राजस्व ला सकती है अथवा पीएसयू से लाभांश वृद्धि अधिक हो सकती है क्योंकि अर्थव्यवस्था के लुच्ची दर पर विकास करने का अनुमान है।

## 2. पूंजी प्राप्तियां

### (क) ऋणों और अग्रिमों की वसूली

28. केंद्र सरकार द्वारा की गई क्रमिक अमध्यस्थता तथा ऋण समकेन एवं ऋण माफी योजना के कारण राज्यों से प्राप्त होने वाली ऋण की निवल वसूली में 12वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के दौरान गिरावट आयी है। तथापि, 12वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि समाप्त होने के चलते ऋण माफी योजना प्रचालन में नहीं होगी और इसलिए राज्यों से ऋणों की वसूली में बढ़ोत्तरी का रुख देखा गया है।

29. ब.अ. 2011-12 में ऋणों और अग्रिमों की वसूली 15,020 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया था। यह अनुमानित उच्च प्राप्ति मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम को उसके अधिप्रापण प्रचालन के लिए दिए गए अल्पावधिक ऋणों की वसूली के कारण थी। इसका सं.अ. 2011-12 और ब.अ. 2012-13 में क्रमशः 14,258 करोड़ रुपये और 11,650 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वर्ष 2013-14 और 2014-15 में प्राप्ति का यह घटक केवल 10,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है क्योंकि सरकार निवल उधार (राज्यों को विदेशी ऋण देने हेतु की गई परस्पर व्यवस्था को छोड़कर) देने को प्रोत्साहन नहीं देगी।

### (ख) अन्य ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां

30. सरकारी पीएसयू में किए गए विनिवेश इस शीर्ष के तहत प्राप्तियों के मुख्य स्रोत हैं। राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) इसलिए सृजित की गई थी कि इस निधि के तहत उन निधि प्रबंधकों द्वारा विनिवेश की प्राप्तियां और संचित निवेश इसमें रखे जा सकें जो 2008-09 तक सरकार को कर-भिन्न राजस्व के रूप में प्रतिलाभ देते थे। वर्ष 2009-10 के दौरान सरकार ने 2009-10 से 2011-12 तक के दौरान प्राप्त की गई विनिवेश की प्राप्तियों को पूंजीगत आस्तियां सृजित करने वाले सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के वित्तपोषण के प्रयोजनार्थ इस्तेमाल करने का निर्णय लिया था।

तदनुसार, विनिवेश प्राप्तियों को ग्रामीण रोजगार, सिंचाई अवसंरचना, शहरी और ग्रामीण अवसंरचना से जुड़े चुनिंदा प्लेगशिप कार्यक्रमों पर किए गए व्यय को आंशिक रूप से पूरा करने हेतु प्रयुक्त किया जा रहा है। साथ ही, राष्ट्रीय निवेश निधि के जरिए पहले किए गए निवेश के प्रतिलाभों को उन चुनिंदा सामाजिक स्कीमों के वित्तपोषण में लगाना जारी है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देती हैं और लाभप्रद तथा पुनरुद्धारकारी सीपीएसई की पूंजी निवेश की जरूरतें पूरी करते हैं।

31. ब.अ. 2011-12 में विनिवेश प्राप्तियों का अनुमान 40,000 करोड़ रुपये लगाया गया था। किंतु विश्व भर में व्याप्त अनिश्चितता ने भारत में पूंजी बाजार पर असर डाला है। अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तरह ही भारत में भी सुरक्षित रहने का रुख देखा गया जिसकी परिणति मुद्रा में मूल्यहास और बाजार पूंजीकरण में गिरावट के रूप में हुई। अतः विनिवेश कार्यक्रम 2011-12 के दौरान काफी हद तक मंद हुआ और तदनुसार, सं.अ. 2011-12 में यह 13,895 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

32. वर्ष 2012-13 में सरकार ने पहले लिए गए निर्णय को संशोधित किया है और विनिवेश की प्राप्तियां 2009-10 से 2011-12 के दौरान की तरह ही कार्यक्रम व्यय के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध होंगी। 13वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि विनिवेश प्राप्तियों को सरकारी व्यय के वित्तपोषण हेतु इस्तेमाल करना जारी रखा जाना चाहिए। यह स्मरणीय है कि 2011-12 के एमटीएफपी विवरण में इस घटक के तहत प्राप्तियां 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः 30,000 करोड़ रुपये और 25,000 करोड़ रुपये रहने की कल्पना की गई थी। ये प्राप्तियां ब.अ. 2012-13 में कल्पित की गई हैं और 2013-14 के लिए अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2014-15 के लिए कार्यक्रम व्यय के वित्त पोषण हेतु किसी भी विनिवेश प्राप्ति की कल्पना नहीं की गई है। तथापि, कार्यक्रम व्यय के वित्तपोषण हेतु विनिवेश प्राप्तियों के इस्तेमाल को समाप्त करने की स्थिति में 2013-14 में अनुमानित राजकोषीय घाटा उस सीमा तक अधिक होगा। 2012-13 और 2013-14 के लिए अनुमानित उपर्युक्त प्राप्तियां संबंधित वर्ष हेतु स.घ.उ. की 0.3 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत बैठती हैं जो 13वें वित्त आयोग द्वारा स.घ.उ. के 0.8 प्रतिशत और 0.9 प्रतिशत के स्तर पर अनुमानित प्राप्तियों से बहुत कम हैं। इन प्राप्तियों से सरकार को मध्यावधिक संदर्भ की चौखट में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया में गति लाने में मदद मिलेगी। अर्थव्यवस्था में पूंजी बाजार की स्थिति और विद्यमान बृहत आर्थिक मापदंडों पर निर्भर रहते हुए ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी दोनों जोखिम संबंधित वर्षों में विनिवेश कार्यक्रम के अनुमानित स्तर के सफलतापूर्वक पूरे होने से जुड़े होते हैं।

33. वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान जब पूर्ववर्ती एनआईएफ के तौर तरीकों को आस्थगित रखा गया था, सरकार द्वारा 36,039 करोड़ रुपये की विनिवेश प्राप्तियां जुटाए जाने का अनुमान है। संयोग से, इसी अवधि के दौरान, सरकार द्वारा

सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और नाबार्ड समेत अन्य वित्तीय संस्थाओं के पूंजीकरण में 36,316 करोड़ रुपये का निवेश किए जाने का अनुमान है। सरकार द्वारा किए गए विनिवेश प्राप्तियों के इस्तेमाल का विश्लेषण करते समय इस सूचना को ध्यान में रखा जा सकता है। इस तरह, उपर्युक्त पैटर्न विभिन्न पोर्टफोलियों में सरकार की आस्तियों के पुनःआवंटन परिलक्षित करता है।

#### (ग) उधार-सरकारी ऋण और अन्य देनदारियां

34. जैसाकि बजट 2010-11 में घोषणा की गई थी, सरकार ने मार्च, 2012 में प्रास्थिति पत्र का वित्तीय संस्करण प्रकाशित किया है, जिसमें सरकार की ऋण स्थिति का विश्लेषण और आने वाले वर्षों में संभावित वित्तीय परिदृश्य का ब्यौरा दिया गया है। केंद्र सरकार की समग्र ऋण और देनदारियों में से, 92.2 प्रतिशत घरेलू ऋण हैं और केवल 7.8 प्रतिशत विदेशी ऋण है। इसके अलावा, सामान्य सरकार के ऋण में विदेशी ऋण का अनुपात घटकर 5.9 प्रतिशत पर आ गया है।

35. जैसाकि हाल के वर्षों में सरकार के घाटे का वित्तपोषण मुख्यतया बाजार निर्धारित ब्याज दरों पर दिनांकित प्रतिभूतियों, जिन्हें नीलामी के जरिए जुटाया जाता है, के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। सरकार के लिए वित्तपोषण के अन्य स्रोतों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) को निर्गमित प्रतिभूतियों, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेन्सियों से विदेशी ऋण, अल्पावधि हुंडियाँ और सरकार के लोक लेखे में निवल अनुवृद्धि शामिल है।

36. 2011-12 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए बाजार उधार कार्यक्रम को दो बार संशोधित करना पड़ा। तदनुसार, ब.अ. 2011-12 में 3,43,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवल आधार के अतिरिक्त, 92,872 करोड़ रुपए जो सघउ का 1 प्रतिशत है, की अतिरिक्त राशि इस लिखत के जरिए जुटाई गई। 2011-12 के दौरान राजकोषीय हुंडियों की नीलामी के जरिए उधार प्राप्ति में 1.01 लाख करोड़ रुपए की भी बढ़ोत्तरी की गयी, जहां राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी के कारण लगभग 1.09 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता हुई, वही शेष बढ़ोत्तरी अन्य वित्तपोषण मदों में ब.अ. 2011-12 की तुलना में कमी के कारण हुई। साथ ही, एनएसएसएफ में नकदी की कमी और 2012-13 में सरकार की पहली तिमाही की नकद आवश्यकताओं को पूरी करने हेतु वर्ष के अंत में नकद अधिशेष के निर्माण की आवश्यकता भी इसकी वजह रही। उधार में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद सरकार ने 2011-12 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए अपना उधार कार्यक्रम बाजार में व्यवधान डाले बिना पूरा किया। सख्त मौद्रिक नीति, व्याप्त नकदीकरण की स्थिति और अधिक उधार के वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आय में कमी आई है। 2011-12 में दिनांकित प्रतिभूतियों की प्रारंभिक नीलामी की भारत औसत आय 2010-11 के 7.9 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गई।

37. ब.अ. 2012-13 में लगभग 93 प्रतिशत घाटे का वित्तपोषण दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए होने का अनुमान है। 2012-13 में निजी क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर खुले बाजार से निवल उधार का अनुमान किया गया है। इस संबंध में सरकारी ऋण के प्रास्थिति पत्र, मार्च 2012 का विस्तृत विश्लेषण किया गया। बअ 2012-13 में दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए निवल उधार के सं.अ. 2011-12 के सघउ के 4.9 प्रतिशत से मामूली रूप से गिरकर 4.8 प्रतिशत हो का अनुमान है। ब.अ. 2012-13 में निरपेक्ष दृष्टि से इसके सं.अ. 2011-12 के 4.36 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 9.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4.79 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बैंक जमाओं में बढ़ती प्रवृत्ति के पूर्वानुमान के साथ ब.अ. 2012-13 में अनुमानित बाजार उधार के बैंकिंग प्रणाली के साथ समग्र जमाओं के अनुपात के रूप में सं.अ. 2011-12 के मुकाबले गिरावट होने का अनुमान है। घाटे के वित्तपोषण के अन्य स्रोतों का ब्यौरा प्राप्ति बजट में दर्शाया गया है।

38. सरकारी ऋण संबंधी प्रास्थिति पत्र में यह व्याख्या की गई है कि केन्द्र सरकार के ऋण और देयताओं का लेखांकन करते समय केन्द्र सरकार के घाटे के वित्तपोषण हेतु उपयोग न की गई राशि को सरकार की देयता सही-सही दर्शाने हेतु लिया जाना चाहिए। एनएसएसएफ के संघटक जिन्हें राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, को केन्द्र सरकार की देयताओं के परिकलन के प्रयोजन से अलग कर दिया गया है। इसी प्रकार, बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत जुटाए गए ऋण को जिसे सरकारी घाटे के वित्तपोषण हेतु अनुपलब्ध समतुल्य पृथक नकद का सहारा होता है, केन्द्र सरकार के ऋण और देयताएं तय करते समय समायोजित भी किया गया है। प्राप्ति बजट के अनुबंध 5क में वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी ऋण के साथ दर्शाई गई देयताओं से इन समायोजनों के साथ केन्द्र सरकार का अनुमानित सघउ-ऋण अनुपात सं.अ. 2011-12 में 45.7 प्रतिशत और ब.अ. 2012-13 में 45.5 प्रतिशत होगा। 2013-14 में सघउ के 4.5 प्रतिशत और 2014-15 में सघउ के 3.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के अनुमानित स्तर के साथ अनुमानित सघउ-ऋण अनुपात क्रमशः 44.0 प्रतिशत और 41.9 प्रतिशत होगा। ये अनुमान यह दर्शाते हैं कि सघउ-ऋण अनुपात 13वें वित्त आयोग द्वारा 2014-15 के लिए 44.8 प्रतिशत के सिफारिश किए गए स्तर से एक वर्ष पहले 2013-14 में नीचे आ जाएगा।

### 3. कुल व्यय

#### (क) राजस्व खाता

##### (i) आयोजना राजस्व व्यय

39. सरकार को 2008-09 में और 2009-10 में अवसंरचना क्षेत्र में माँग और निवेश बढ़ाने हेतु अपने आयोजना व्यय में पर्याप्त बढ़ोत्तरी करनी पड़ी। यह निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के प्रभाव को कम से कम करने हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों का भाग था। इस तथ्य

को देखते हुए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2009-10 और 2010-11 के दौरान 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, से यह साबित होता है कि सरकार के बढ़ते आयोजना व्यय से अर्थव्यवस्था के शीघ्र और व्यापक पुनरुज्जीवन में सहायता मिली है। आयोजना राजस्व व्यय 2010-11 के 3,14,232 करोड़ रुपए से बढ़कर सं.अ. 2011-12 में 3,46,201 करोड़ रुपए हो गया जो 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसे इस संघटक के लिए 2008-09 से 2010-11 तक के दौरान लगभग 23 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में देखा जा सकता है। पुनः बअ 2012-13 में आयोजना राजस्व व्यय के सं.अ.2011-12 के मुकाबले 21.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4,20,513 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। राजस्व व्यय (पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों से भिन्न) में वृद्धि के स्तर को आगामी वर्षों में प्रभावी राजस्व घाटा कम करने के वांछित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कम किया जाना है।

40. उपर्युक्त आवंटन के साथ आयोजना व्यय हेतु प्रावधान बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुमानित व्यय परिव्यय से अधिक होगा। आवंटनों में पर्याप्त वृद्धि से परिव्ययों को परिणामों में परिवर्तन, योजनाओं को मुख्यधारा में लाना और आयोजना स्कीमों की संख्या को कम करना जैसे मुद्दे उठेंगे जिससे कि सरकार की केन्द्रित प्राथमिकताएं प्रदर्शित होंगी जिन्हें मध्यावधि में आधार परिदृश्य से मॉनिटर किया जा सकता है।

#### (ii) आयोजना भिन्न राजस्व व्यय

41. आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय जिसके अंतर्गत मुख्यतया वेतन, पेंशन, रक्षा सेवाएं, ब्याज भुगतान और राज्यों के सांविधिक अनुदान आते हैं, की वजह से सरकार के राजस्व खाते में ढांचात्मक असंतुलन आता है। इस संघटक में 2008-09 और 2009-10 के दौरान छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव और वैश्विक आर्थिक संकट के कारण 2007-08 के पश्चात् तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। जहाँ 2009-10 के दौरान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां सघउ का 8.9 प्रतिशत की, वहीं 2009-10 में आयोजना भिन्न व्यय सघउ का 10.2 प्रतिशत हो गया। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का यह स्तर स्थायी नहीं है और सरकारी राजस्व के वर्तमान स्रोत इस पूर्णतः वित्तपोषित नहीं कर पाएंगे। अंतः इस संघटक के वित्तपोषण के लिए संसाधनों को उधार पर लिए जाने की आवश्यकता हुई है। इन संघटकों के लिए व्यय संबंधी वचनबद्धता को पूरा करने हेतु, उधार पर लिए गए संसाधनों का उपयोग वांछनीय नहीं होगा। सब्सिडी सुधार में सघउ वृद्धि और उपायों की तुलना में वेतन और पेंशन संबंधी व्यय में अनुमान से कम वृद्धि से ऐसा अनुमान है कि बअ 2012-13 में समग्र आवंटन सं.अ.2011-12 के सघउ के 9.2 प्रतिशत के मुकाबले सघउ का 8.5 प्रतिशत होगा। तथापि, इन आवंटनों का अनुपालन करना और वर्ष के दौरान अनुदानों की पूरक माँगों के जरिए पर्याप्त संवर्धन न किए जाने की चुनौती है। वास्तव में इन अनुमानों में संबंधित जोखिम कारक है।



42. निरपेक्ष दृष्टि से बजट 2012-13 में आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय सं. 2011-12 के 8,15,740 करोड़ रुपए से 6.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 8,65,596 करोड़ रुपए हो गया। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय की प्रमुख मदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

**(क) ब्याज अदायगियाँ**

43. 2008-09 और 2009-10 के दौरान राजकोषीय प्रसारणशील नीति के दो वर्ष और वृद्धि में कमी तथा करों की कम प्राप्ति से केन्द्र सरकार के निवल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान में तीव्र वृद्धि हुई। 2004-05 से 2007-08 की राजकोषीय समेकन अवधि के दौरान केन्द्र सरकार के निवल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान 2004-05 के 56.5 प्रतिशत से गिरकर 2007-08 में 38.9 प्रतिशत हो गया। 2009-10 में यह बढ़कर 46.7 प्रतिशत हो गया। यह गिरावट 2007-08 और 2009-10 में एमएसएस संबंधी ब्याज भुगतान के प्रभाव को घटाने के पश्चात् अधिक देखी जा सकती है।

44. 2010-11 में राजकोषीय समेकन प्रक्रिया के प्रारम्भ के साथ यह प्रतिशत 2010-11 के दौरान बढ़कर 41.1 प्रतिशत हो गया। तथापि, 2011-12 के दौरान राजकोषीय घाटे में वृद्धि और लक्षित कर राजस्व में कमी से सं.अ. 2011-12 में यह पुनः बढ़कर 42.9 प्रतिशत हो गया। इससे यह इंगित होता है कि राजकोषीय दृष्टि से एक या दो वित्तीय वर्ष के लिए गिरावट से भविष्य में विकासात्मक व्यय के संसाधनों में कमी आ सकती है क्योंकि ब्याज भुगतान की वजह से सरकारी निवल कर राजस्व से अन्य व्यय के लिए कटौती करनी होगी।

45. आने वाले वर्षों में सरकार को इस घटक के तहत संभावित किसी गिरावट के विरुद्ध सतर्क रहना है। बजट अनुमान 2012-13 में राजकोषीय घाटे में कमी के साथ केन्द्र को निवल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान 41.5 प्रतिशत तक कम होगा। मध्यम आवधिक परिप्रेक्ष्य में परिकल्पित राजकोषीय घाटे और इस संकल्पना के साथ कि बढ़ता हुआ ऋण वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाएगा, वर्ष 2013-14 में इस अनुपात के 39.0 प्रतिशत तक सुधरने का अनुमान है जोकि संकट-पूर्व-स्तर के करीब हो जाएगा और आगे चलकर 2014-15 में 35.9 प्रतिशत सीमित हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान मध्यम तौर पर सघट के तीन प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस अनुमान से जुड़ा एक जोखिम आगामी वर्षों में ब्याज दर में महत्वपूर्ण बदलाव है या अनुवर्ती वर्षों में अनुमान से कहीं ज्यादा राजकोषीय घाटा होना है।

**(ख) रक्षा सेवाएं**

46. 2010-11 में 92,061 करोड़ रुपए की तुलना में संशोधित अनुमान 2011-12 के दौरान राजस्व लेखे में रक्षा सेवाओं का व्यय बढ़कर 1,04,793 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। जोकि 13.8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। राजस्व लेखे में विकास की बढ़ती

दर को सुधार कर कम किए जाने की जरूरत है। तदनुसार संशोधन अनुमान 2011-12 की तुलना में बजट अनुमान 2012-13 में 1,13,829 करोड़ रुपए तक अर्थात् 8.6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। 2013-14 और 2014-15 तक इसके 7 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। संशोधित अनुमान 2011-12 से बजट अनुमान 2012-13 में इस घटक के 1.2 प्रतिशत से घटकर 1.1 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। आगे यह भी उम्मीद है कि 2013-14 और 2014-15 में घटते हुए यह घटक सघट के 1.0 प्रतिशत तक सीमित हो जाए।

**(ग) प्रमुख सब्सिडियां**

47. समग्र संदर्भों में प्रमुख सब्सिडियों (खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम) के प्रावधान वर्ष 2010-11 में 1,64,516 करोड़ रुपए थे जो पर्याप्त वृद्धि के साथ सं. अ. 2011-12 में 2,08,503 करोड़ रुपए हो गए हैं यह 26.7 प्रतिशत की वृद्धि है। सब्सिडी से जुड़े व्यय का बढ़ता हुआ यह स्तर साल-दर-साल धारणीय न होगा। सब्सिडी व्यय की बढ़ती मात्रा के काबू में लाने के लिए सरकार जरूर नीतिगत और प्रशासनिक उपायों पर अमल कर रही है। सब्सिडियों को ज्यादा जाएगी और बेहतर तरीके से लक्ष्यबद्ध करना और यूआईडीएआई की मदद से सीधे नकद अन्तरण करना ही इस दिशा में आगे बढ़ने में सहायक हो सकता है।

48. सं. अ. 2011-12 में प्रमुख सब्सिडियों के प्रावधान 2,08,503 करोड़ रुपए से घटकर बजट अनुमान 2012-13 में 1,79,554 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसी प्रकार कुल सब्सिडियों का सं. अ. 2011-12 में 2,16,297 करोड़ रुपए से घटकर बजट अनुमान 2012-13 में 1,90,015 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। यह सघट की 1.9 प्रतिशत राशि बनती है। इसके मूल में यह मान्यता है कि आवश्यक नीतिगत उपाय पेट्रोलियम और उर्वरक सब्सिडी को चालू वर्ष की अपेक्षाओं से एक स्तर नीचे रखने में मददगार होंगे। इन प्रावधानों का प्रभावी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए उपायों तथा साधनों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाना जरूरी है और भौतिक व सामाजिक अवसंरचना में बढ़ रहे निवेश के मद्देनजर आगे और गुंजाइश बनाए रखने के लिए इस व्यय को खर्च किए जाने की जरूरत है। सब्सिडी भुगतान का मौजूदा स्तर बहुत समय तक नहीं चलाया जा सकता और इस क्रम में सरकार कतिपय उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी मैकेनिज्म की शुरुआत, पेट्रोल मूल्यों का अ-विनियमीकरण जैसे कई उपायों को अमल में ला रही है। ये उपाय प्रमुख सब्सिडियों का व्यय घटाने में काफी हद तक सहायक रहे हैं। 2012-13 में सघट के 1.9 प्रतिशत से घटाकर सब्सिडी व्यय को 2014-15 तक सघट के 1.6 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए डिलीवरी मैकेनिज्म में पर्याप्त सुधार के साथ-साथ सब्सिडी नीति को नए सिरे से चुस्त-दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। इस क्रम में होने वाली कोई छोटी सी चूक भी भविष्य में राजकोषीय समेकन प्रक्रिया को धक्का पहुंचा सकती है और विकास व्यय के लिए नियत वित्तीय संसाधनों पर बोझ बन सकती है।

49. सरकार ने पेट्रोलियम तथा उर्वरक सब्सिडियां प्रतिभूतियों के बजाए नकद सहायता के रूप में मुहैया कराने की प्रक्रिया को दृढ़तापूर्वक संस्थापित किया है। सरकारी सब्सिडी नकद रूप में देने की अपनी प्रक्रिया पर सरकार 2011-12 के दौरान भी कायम है।

50. एफसीआई को बाजार से जुड़ी दरों पर कार्यरत पूंजी ऋण सहायता मुहैया कराने की प्रक्रिया से उच्च लागत वाली निधियों पर उसकी निर्भरता घटाने में मदद मिलती है। आगे चलकर इससे खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए ब्याज लागत को घटाने में सहायता मिलेगी। यह प्रक्रिया आगामी वर्षों में भी जारी रहेगी। इसके बाद एफसीआई अपनी प्रशासनिक लागत के सामंजस्य पूर्ण समायोजन की संभावनाएं भी तलाश सकता है और इसी हाल में राज्यों से भी अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्र को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की समग्र लागत को घटाने के लिए विकेंद्रित प्रापण प्रणाली में हाथ बंटाएं।

#### (घ) राज्यों तथा संघ शासित राज्यों को गैर-योजना अनुदान

51. इस श्रेणियों के अन्तर्गत 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान संस्तुत किए गए हैं और बजट अनुमान 2012-13 में ये उपलब्ध कराए गए हैं तथा 2013-14 और 2014-15 के अनुमानों में इनका उपदान किया गया है।

उत्तर-अवमूल्यन गैर योजना राजस्व घाटा (एनपीआरडी), निष्पादन प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा, परिणाम-सुधार, पर्यावरण सम्बद्ध, सड़कों का रख-रखाव, राज्य विशिष्ट, स्थानीय निकाय, आपदा राहत।

52. 13वें वित्त आयोग की निर्णयावधि के दौरान 3,18,581 करोड़ रुपए के कुल अनुदान संस्तुत किए गए थे और यह 12वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत राशि से कहीं ज्यादा राशि है। इसमें राज्यों को केंद्रीय करों के अंतरण की उच्चतर प्रतिशतता भी शामिल होगी जिनका परिणाम केंद्र सरकार के लिए अपने व्यय हेतु राजस्व संसाधनों की कमतर उपलब्धता होगा। तदनुसार यह 13वें वित्त आयोग पंचाट अवधि के दौरान आने वाले वर्षों में राजस्व घाटे में कमी को प्रभावित करेगा।

53. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में कुल आयोजना भिन्न अनुदानों में 2010-11 में 49,790 करोड़ रुपए से बढ़ोतरी होकर सं.अ. 2011-12 में 55,322 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है। केन्द्र के सम्बन्ध में सघउ की प्रतिशतता तथा निवल कर राजस्व दोनों ही दृष्टियों से, इसके सं.अ. 2011-12 में भी 2010-11 के उसी स्तर पर रहने का अनुमान है। ब.अ. 2012-13 में इसके 16.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए 64,211 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

54. 13वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों तथा सम्भाव्य अन्य आयोजना भिन्न अनुदानों के आधार पर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से सम्बद्ध कुल आयोजना भिन्न अनुदानों के 2013-14 तथा 2014-15 में सघउ के 0.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

#### (ङ) पेंशन

55. छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, पेंशन पर व्यय में 2007-08 में 24,261 करोड़ रुपए से महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होकर 2010-11 में 57,405 करोड़ रुपए हो गयी जो लगभग 33.3 प्रतिशत की सम्मिश्र वृद्धि दिखाता है। पेंशन व्यय जो 2007-08 में केन्द्र के निवल कर राजस्व का 5.5 प्रतिशत और सघउ का 0.5 प्रतिशत था, उसमें वृद्धि होकर वह 2010-11 में क्रमशः 10.1 प्रतिशत तथा 0.7 प्रतिशत हो गया। बकाया राशियों का भुगतान करने से इनकी प्रतिशतता सं.अ. 2011-12 में 8.7 प्रतिशत तथा 0.6 प्रतिशत के मामूली स्तर पर पहुंचने की आशा है और ब.अ. 2012-13 में पुनः निवल कर राजस्व के 8.2 प्रतिशत पर पहुंचने की आशा है।

56. इस अनुमान से कि आगामी वर्षों में पेंशन सम्बन्धी व्यय 8 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, अनुमान है कि पेंशन भुगतान में 2014-15 तक गिरावट होकर यह 0.5 प्रतिशत हो जाएगा और यह घटकर उसी वर्ष केन्द्र के निवल कर राजस्व का 6.5 प्रतिशत तक हो जाएगा। उक्त अनुमान आगामी वर्षों में बड़ी मात्रा में पेषण दर की जोखिम से जुड़ा है जिसके परिणामस्वरूप यह अनुमानित व्यय से अधिक होगा।

#### ख पूंजी लेखा

##### (i) पूंजी परिव्यय

57. कुल पूंजी व्यय का ब.अ. 2012-13 में 2,04,816 करोड़ रुपए का अनुमान है जो सं.अ. 2011-12 की तुलना में 30.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज करता है। आयोजना पूंजी व्यय में 2010-11 में 64,797 करोड़ रुपए से बढ़ोतरी होकर यह सं.अ. 2011-12 में 80,404 करोड़ रुपए तथा ब.अ. 2012-13 में 1,00,512 करोड़ रुपए हो गया तथा जो दो वर्ष की अवधि में 24.5 प्रतिशत की सम्मिश्र वृद्धि दिखाता है। सामान्य सरकार के समेकित लेखे में पूंजी व्यय का अधिकांश भाग केन्द्र सरकार से राज्यों अथवा अन्य कार्यान्वयक एजेंसियों से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में दिखाया जाता है।

58. यह सामान्य सरकार स्तर पर पूंजी निवेश का कम प्रदर्शन है। ब.अ. 2012-13 में कुल पूंजी व्यय (जिसमें पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान शामिल है) 3,69,488 करोड़ रुपए अनुमानित है जो सघउ का 3.6 प्रतिशत है। सरकार का प्रयास होगा कि आगामी मध्यावधि में इस प्रतिशत को उत्तरोत्तर रूप से बढ़ाए, मध्यावधि राजकोषीय आयोजना में, इस प्रतिशत में बढ़ोतरी होकर इसके 2013-14 में 3.7 प्रतिशत और 2014-15 में 3.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसे समग्र व्यय में अनुमानित कमी के रूप में देखा जा सकता है जो ब.अ. 2012-13 में सघउ के 14.7 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 14.1 प्रतिशत तथा 2014-15 में सघउ का 13.6 प्रतिशत हो गया। इसके परिणामस्वरूप, समग्र व्यय में व्यय के इन संघटकों के प्रतिशत हिस्से में बढ़ोतरी देखी गयी और जो सं.अ.

2011-12 में 22.3 प्रतिशत से ब.अ. 2012-13 में 24.4 प्रतिशत तथा पुनः 2013-14 एवं 2014-15 में क्रमशः 26.2 प्रतिशत और 28.7 प्रतिशत हो गया। वर्तमान में क्षमता वर्धन सार्वजनिक निजी भागीदारी का रूप ले रहा है। साथ ही, केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) अपने पूंजी व्यय के बड़े भाग की पूर्ति आन्तरिक बजट बाह्य संसाधनों (आईईबीआर) के माध्यम से कर रहे हैं। सीपीएसयू के आईईबीआर (रेलवे सहित) में 2010-11 में 1,56,893 करोड़ रुपए से बढ़ोतरी होकर सं.अ. 2011-12 में 2,11,359 करोड़ रुपए और ब.अ. 2012-13 में 2,25,485 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

59. आयोजना भिन्न व्यय में मुख्यतः रक्षा व्यय शामिल है। रक्षा पूंजी व्यय के सं.अ. 2011-12 में 66,144 करोड़ रुपए से बढ़कर ब.अ. 2012-13 में 79,579 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह 20.3 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। समग्रतः आयोजना भिन्न व्यय के सं.अ. 2011-12 में 76,376 करोड़ रुपए से बढ़ोतरी होकर 1,04,304 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है जो 36.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है। रक्षा पूंजी परिव्यय में बढ़ोतरी के अलावा, इस वृद्धि मुख्यतः अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में कोटा बढ़ोतरी हेतु दिए गए सरकारी अंशदान की वजह से है। ब.अ. 2012-13 में इस प्रयोजनार्थ 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

#### (ii) ऋण और अग्रिम

60. राज्यों द्वारा बाजार से सीधे घरेलू ऋणों की संविदा किए जाने से निवल ऋणों की मध्यावधि में घटने की आशा है। तथापि राज्यों को विदेशी ऋणों की प्राप्ति केन्द्र सरकार के जरिए होती रहेगी। ब.अ. 2012-13 में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता (ईएपी) ऋण के रूप में 11,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। विदेशी सरकारों को आयोजना भिन्न ऋण ब.अ. 2012-13 में 550 करोड़ रुपए होना अनुमानित है।

61. आयोजना भिन्न ऋण केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रदान किए जाते हैं जिनमें निवेशों के लिए बजटीय सहायता, पुनर्संरचना/पुनरुज्जीवन तथा स्वोच्छिक सेवा निवृत्ति योजना/स्वोच्छिक पृथभूरण योजना शामिल है। तथापि, ये चरण महत्वपूर्ण स्वरूप के नहीं हैं।

#### 4. सघउ विकास

62. इस विवरण में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी त्वरित अनुमान 2010-11 तथा अग्रिम अनुमान 2011-12 के लिए सघउ आंकड़ों का उपयोग किया गया है। आंकड़ों की उपर्युक्त श्रृंखला के अनुसार, 2010-11 के दौरान कारक लागत पर वार्षिक वास्तविक सघउ विकास 2004-2005 के स्थिर मूल्यों पर 2009-10 के दौरान सदृश 8.4 प्रतिशत पर बना रहा। 2011-12 के लिए सीएसओ से जारी अद्यतन आंकड़ों में वास्तविक सन्दर्भ में विकास दर को 6.9 प्रतिशत दिखाया गया है और सम्भाव्य मुद्रास्फीति पर विचार करने के बाद, 2011-12 के लिए

सघउ विकास दर मौजूदा बाजार मूल्यों पर) 16.1 प्रतिशत अनुमानित है। इस प्रकार 2011-12 के लिए सघउ (मौजूदा बाजार मूल्यों पर) अब ब.अ. 2011-12 में 89,80,860 करोड़ रुपए भी तुलना में 89,12,179 करोड़ रुपए अनुमानित है।

63. 2012-13 के सम्बन्ध में यह आशा है कि वास्तविक सघउ विकास दर 7.6 प्रतिशत(+/- 25 आधार बिन्दु) पर होगी। सम्भाव्य मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते के बाद, 2011-12 के लिए सघउ विकास (मौजूदा बाजार मूल्यों पर) के 14.0 प्रतिशत होना अनुमानित है जिसके परिणाम स्वरूप सघउ 101,59,884 करोड़ होगा, 2012-13 से 2013-14 के सम्बन्ध में मध्यावधि में सम्भाव्य मुद्रास्फीति तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सरकार के 9 प्रतिशत की औसत विकास दर बनाए रखने के प्रयास को ध्यान में रखने के बाद मौजूदा बाजार मूल्यों पर सघउ विकास 2013-14 के लिए 15.0 प्रतिशत तथा 2014-15 के लिए 15.5 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।

#### ग. निम्नलिखित के सम्बन्ध में निरन्तरता के बने रहने का मूल्यांकन

##### (i) राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय के बीच संतुलन

64. सरकार व्यय का मौजूदा राजस्व वर्गीकरण असंतुलन के संरचात्मक संघटन पर जोर नहीं देता को स्वरूप में क्षयोन्मुख है। राजस्व लेखे में शेष निर्धारण का उद्देश्य क्षयोन्मुख व्यय की पूर्ति हेतु सुधार संसाधनों की अनुमति प्रदान करना था। राजस्व लेखे में शेष को सरकार के तीन स्तरों अर्थात् केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों के समेकित खातों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। यह भारतीय सदर्थ में अधिक प्रसंगिक होगा क्योंकि अन्तर-सरकारी अन्तरण की बड़ी राशि केन्द्र से राज्य को तथा राज्यों से स्थानीय निकायों को अन्तरित होती है। यह राजस्व खाते में असन्तुलन की सही तस्वीर को विकृत करता है। तब कोई भी पृथक तरीके से सरकार के विभिन्न स्तरों के राजकोषीय लेखे पर ध्यान देता है। मौजूदा सूचना प्रणाली केन्द्र तथा राज्य स्तर पर परितुलन आंकड़े उपलब्ध कराती है। तथापि यह विश्लेषण करना अनुचित नहीं होगा कि केन्द्र सरकार के राजस्व लेखे में मौजूदा कितना असन्तुलन सरकार के अन्य स्तरों तथा अन्य अनुदानग्राही निकायों की पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के स्वरूप में किए गए अन्तरणों की वजह से होता है।

65. 2011-12 के बजट में प्रभावी राजस्व घटिका विचार सरकार के राजस्व लेखे में संरचनात्मक असंतुलन की वास्तविक तस्वीर को दिखाने हेतु सामने आया था, इस विचार को और ठोस रूप देने के लिए सरकार एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन का रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रभावी राजस्व घाटे को 2014-15 तक समाप्त करना अधिदेशित है, यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार के राजस्व लेखे में संरचनात्मक असंतुलन को पूरी ईमानदारी से सुलझाया जा रहा है। पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के स्वरूप में राजस्व लेखे में व्यय को ध्यान में रखने के बाद जो ब.अ. 2012-13 के सघउ के 1.6 प्रतिशत के स्तर पर है,

केन्द्र सरकार का प्रभावी राजस्व घाटा सं.अ. 2011-12 में 2.9 प्रतिशत से घटकर ब.अ.2012-13 में सघउ के 1.8 प्रतिशत होना अनुमानित है। यद्यपि व्यय के उत्पादक क्षेत्र की तरफ पुनः मुड़ने की प्रक्रिया दिखाई देती है, इसलिए सरकार का प्रयास इस घाटे को 2014-15 तक समाप्त करने का होगा।

66. 2013-14 तथा 2014-15 के अनुदानों में कुल व्यय में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु पूंजी व्यय तथा अनुदानों का अनुपात क्रमिकता से बढ़ा है। इसके लिए विवेकपूर्ण नीति और प्रशासनिक पहलें जरूरी हैं। इसके परिणास्वरूप समग्र व्यय में व्यय के इन संघटनों प्रतिशत हिस्सेदारी में सं.अ.2011-12 में 22.3 प्रतिशत से बढ़ोतरी होकर ब.अ. 2012-13 में 24.4 प्रतिशत और पुनः 2013-14 तथा 2014-15 में क्रमशः 26.2 प्रतिशत तथा 28.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। व्यय के इस अनुमानित स्तर से प्रभावी राजस्व घाटे का अनुमान 2013-14 में सघउ के 1.0 प्रतिशत तक घटना अनुमानित है और 2014-15 तक इसे पूरी तरह समाप्त करना है। 2014-15 तक प्राप्य प्रभावी राजस्व घाटे के उन्मूलन के लक्ष्य को नीतिगत पहलों तथा प्रभावी क्षमता से प्राप्त किए जाने की दरकार है।

**(ii) उत्पादन परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु बाजार उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों का उपयोग**

67. 2010-11 के दौरान-राजकोषीय समेकन प्रक्रिया की पुनर्बहाली से, कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में आयोजना भिन्न ऋण 2009-10 में 126 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटकर 104 प्रतिशत हो गया। ब.अ. 2011-12 में इसके मामूली रूप से घटकर 103

प्रतिशत पर पहुंचना अनुमानित था तथापि, सब्सिडी सम्बद्ध व्यय और कर प्राप्तियों में गिरावट की वजह से इस प्रतिशत के स.अ.2011-12 में 116 प्रतिशत के खराब स्तर पर पहुंचने की अनुमान है। साथ ही राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में आयोजना व्यय 2010-11 में 101 प्रतिशत से घटकर सं.अ. 2011-12 में 82 प्रतिशत हो गया। इस के परिणात्मस्वरूप आयोजना भिन्न व्यय के लिए उधार लिए गए संसाधनों का उपयोग हुआ।

68. ब.अ.2012-13 में राजकोषीय समेकन प्रक्रिया की पुनर्बहाली के प्रस्ताव के चलते, राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में आयोजना व्यय के 101 प्रतिशत तक सुधार होने का अनुमान है। इससे हम व्यय के संघटन में संरचनात्मक समस्याओं तथा उत्पादन क्षेत्रों की तरफ व्यय को पुनः उन्मुख करने की दिशा की ओर बढ़े हैं। इस मुद्दे को स्थिर आधार पर निपटने की जरूरत है। मध्यावधि दृष्टिकोण में, अनुमान है कि राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में आयोजना व्यय में सुधार होकर यह 2013-14 तथा 2014-15 में क्रमशः 114 प्रतिशत तथा 131 प्रतिशत हो जाएगा। साथ ही कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में आयोजना भिन्न व्यय 2013-14 तथा 2014-15 में घटकर क्रमशः 96 तथा 88 प्रतिशत होने का अनुमान है, यह उधार किए गए संसाधनों के नियोजन में महत्वपूर्ण सुधार दिखाता है। सरकार पुनः प्रयास करेगी कि आयोजना भिन्न व्यय विशेष रूप से आयोजना भिन्न राजस्व व्यय के वित्त पोषण हेतु ऋण प्राप्तियों का उपयोग नहीं करेगी। यह प्रयास सघउ के ऋण अनुपात के कमी लाएगा तथा केन्द्र के निवल कर राजस्व के सम्बन्ध में व्याज उदायगी धीरे धीरे वहनीय स्तर पर जा पहुंचेगी और उधार ली गयी निधियों का विवेकसम्मत उपयोग होगा।

**अनुबंध- I**

**13वें वित्त आयोग के राजकोषीय रोडमैप के साथ एमटीएफपी की तुलना**

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
<b>राजकोषीय घाटा</b>				
एमटीएफपी	5.9	5.1	4.5	3.9
13वां वित्त आयोग	4.8	4.2	3.0	3.0
<b>राजस्व घाटा</b>				
एमटीएफपी	4.4	3.4	2.8	2.0
13वां वित्त आयोग	2.3	1.2	0.0	-0.5
<b>ऋण *</b>				
एमटीएफपी	45.7	45.5	44.0	41.9
13वां वित्त आयोग	52.5	50.5	47.5	44.8

\* इसमें राज्यों को दिए गए एनएसएसएफ ऋण एमएसएस के अन्तर्गत ऋण शामिल नहीं है और मौजूदा विनियम दर पर विदेशी ऋण हेतु परिकलन के लिए है।